



# भारत का राजपत्र

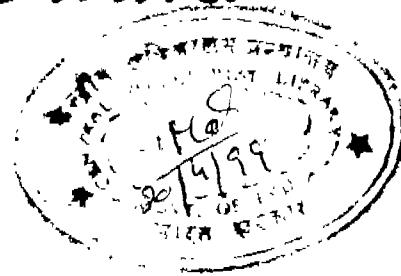
## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 82 ]  
No. 82]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 1999/माघ 23, 1920  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 1999/MAGHA 23, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 107 (अ).— राष्ट्रपति बारा जारी की गई निम्नलिखित

उद्योगण सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है:-

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति, के 0आर० नारायणन को विभार सरकार से रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा प्राप्त अन्य सूचनाओं पर विचार कर समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान इससे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है] के उपर्यों के अनुसार नहीं बताया जा सकता है,

अतः अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्योगण करता हूँ कि मैं:-

॥क॥ उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या प्रतद्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के स्प में अपने हाथ में लेता हैं,

॥ख॥ घोषित करता है कि उक्त राज्य के विधान भण्डल की शक्तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी, और

॥ग॥ निम्नलिखित अनुभोगिक और पारिणामिक उपबंध करता हैं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभाली करने के लिए मुझे आवश्यक या बांधनीय प्रतीत होते हैं,  
अर्थात् :-

॥।॥ इस उद्घोषणा के उपर्युक्त स्पष्ट ॥क॥ के आधार पर अपने हाथ में लिप गप कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के स्प में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा,

॥॥॥ उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को प्रतद्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :-

अनुच्छेद 3 के पस्तुक का उतना भाग जिसने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान भण्डल को निवेश करने से है,

अनुच्छेद 151 के स्पष्ट ॥2॥ का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महासेवा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान भण्डल के समक्ष रखे जाने से है,

अनुच्छेद 163 और 164,

अनुच्छेद 166 के खण्ड ॥३॥ का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मौत्रियों के बीच आवंटन से है,

अनुच्छेद 167,

अनुच्छेद 169 के खण्ड ॥१॥ का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है,

अनुच्छेद 174 का खण्ड ॥१॥ और खण्ड ॥२॥ का उपखण्ड ॥क॥,

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्पालित हैं),

अनुच्छेद 179 का खण्ड ॥ख॥ और ॥ग॥ और उस अनुच्छेद का प्रथम पर्सन्तुक,

अनुच्छेद 180, 181 और 182,

अनुच्छेद 183 का खण्ड ॥ग॥ और उसका पर्सन्तुक,

अनुच्छेद 185,

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलमों और भत्तों से है,

अनुच्छेद 188 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्य से है,

अनुच्छेद 189, 193 और 194,

अनुच्छेद 195 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्यों के वैतन और भत्तों से है,

अनुच्छेद 196 और 198 [जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं],

अनुच्छेद 199 के खण्ड ॥३॥ और ॥४॥,

अनुच्छेद 208 से 211 तक [जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं],

अनुच्छेद 213 के खण्ड ॥१॥ का पस्तुक और खण्ड ॥३॥ का पस्तुक, और

अनुच्छेद 323 के खण्ड ॥२॥ का उतना भाग जिसने का संबंध ज्ञापन सीहत रिपोर्ट के राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है,

॥।।॥ [संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निवेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निवेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थात् जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निवेश लगाया जाएगा, और विशिष्टत्या अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निवेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निवेश लगाया जाएगा,

पस्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक [जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं] अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा वित्तीय अनुसूची के पैरा । से लेकर पैरा 4 तक [जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं] के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड ॥।॥ के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेंगी,

॥ ॥/॥ संविधान में राज्य के विधान मण्डल के या पतवद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के संहृ॥ ॥ के उपर्युक्त इकू में निर्विचित अन्य प्राचिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और बिहार और उड़ीसा साधारण संघ अधिनियम 1917 बिहार और उड़ीसा 1917 का अधिनियम ॥ ॥ जिस रूप में बिहार राज्य में लागू है और साधारण संघ अधिनियम 1897 § 1897 के 10वें का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।

कैम्प कलकत्ता

दिनांक 12-2-1999

(के. आर. नारायण)

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

दिनांक 12-2-1999

[फा. सं.-बी-11013/1/99-सी. एस. आर.]

बी. पी. सिंह, गृह सचिव

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1999

**G. S. R. 107 (E).— The following Proclamation by the President is published for general information:-**

Whereas, I, K.R.Narayanan, President of India, have received a report from the Governor of the State of Bihar and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a

situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I -

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:-
  - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:-

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179  
and the first proviso to that article;

articles 180, 181, and 182, clause  
(c) of article 183 and the proviso  
thereto;

article 185;

so much of article 186 as relates to  
the salaries and allowances of the  
Deputy Speaker of the Legislative  
Assembly;

so much of article 188 as relates to  
a member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to  
the salaries and allowances of Members  
of the Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both  
inclusive);

clauses (3) and (4) of article 199;

articles 208 to 211 (both  
inclusive);

the proviso to clause (1) and the  
proviso to clause (3) of article 213;  
and

so much of clause (2) of article 323  
as relates to the laying of the report  
with a memorandum before the  
Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Bihar and Orissa General Clauses Act, 1917 (Bihar and Orissa Act 1 of 1917) as in force in the State of Bihar, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

Camp Calcutta  
Dated 12-2-1999

K. R. NARAYANAN  
President

— — —  
New Delhi  
Dated 12-2-1999

[F. No.V-11013/1/99-CSR]  
B. P. SINGH, Home Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1999

स. का. नि. 108 (अ).—[ राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश  
सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आगे फरवरी, 1999 के बारहवें  
दिन जारी की गई उपरोक्त के खण्ड [क] के उपरांग [।।] का अनुसरण करते हुए मैं एतम्हाय निम्न घोषणा  
हूँ कि विहार राज्य सरकार के सभी कृत्य और विधान के अधीन या उस राज्य में प्रचलित किसी विधि के  
अधीन उस राज्य के राज्यपाल में नियुक्त या प्रयोक्तव्य सभी व्यक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उपरोक्त के  
खण्ड [क] के अधार पर अपने हाथ में ले रखा है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, नियोजन और नियन्त्रण के  
अध्याधीन रहते हुए, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य पांचों

कैम्प कलकत्ता

दिनांक 12-2-1999

(के. आर. नारायण)

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

दिनांक 12-2-1999

[फा. सं.-वी-11013/1/99-सी. एस. आर.]

बी. पी. सिंह, गृह सचिव

### ORDER

New Delhi, the 12th February, 1999

**G. S. R. 108 (E).— The following Order made by the President  
is published for general information:**

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the  
Proclamation issued on this the 12<sup>th</sup> day of February, 1999  
by me under article 356 of the Constitution of India, I

hereby direct that all the functions of the Government of the State of Bihar and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

Camp Calcutta  
Dated 12-2-1999

K. R. NARAYANAN  
President

—  
New Delhi  
Dated 12-2-1999

[F. No.V-11013/1/99-CSR]  
B. P. SINGH, Home Secy.